जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 48 संख्याः 218 प्रभात कोटा, मंगलवार 23 मई, 2023 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

मॉरिशस कैस्ट्रेल बेहद खूबसूरत फोटोजैनिक पक्षी हैं। वर्ष 1974 में ये एकदम विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे और मात्र चार कैस्ट्रेल बचे थे। फिर, कई दशकों तक चले संरक्षित प्रजनन की बदौलत मॉरिशस में इनकी आबादी एक हजार हो गई। लेकिन, 50 साल बाद इनकी आबादी फिर से घटने लगी और मात्र 350 पक्षी ही बचे। तथापि, इस बार इन पक्षियों को ट्रैवलर्स ट्री नाम के एक वृक्ष से मदद मिली है। युनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में इकॉलजिस्ट एवं मुख्य शोध लेखक विन्सैंट फ्लोरैंस ने बताया कि, ट्रैवलर्स ट्री कैस्ट्रल के मुख्य भोजन, ब्लू टेल्ड डे गैको और मॉरिशस अपलैंड फॉरैस्ट गैको का प्रमुख आवास हैं। शोख रंगों वाली ये छिपकलियां इस वृक्ष की पत्तियों पर आराम फरमाती हैं। इस वृक्ष के पुष्प पराग और फलों से आकर्षित होकर कीट भी आते हैं, जो गैको का प्रिय भोजन हैं। फ्लोरैंस व उनकी टीम ने देखा कि, कैस्ट्रैल के भोजन का 70 प्रतिशत भाग गैको ही हैं। असल में इन छिपकलियों में कैल्शियम काफी ज्यादा होता है जो कैस्ट्रैल के अण्डों को मजबूत बनाने के लिए जरुरी होता है। इन पक्षियों के जो घोंसले ट्रैवलर्स ट्री के आसपास होते हैं उनमें चूज़े ज्यादा होते हैं। लेकिन पाम वृक्ष जैसा दिखने वाला, बाहर से आया यह वृक्ष यहां के मूल वृक्षों के लिए खतरा बन गया है। अब संरक्षणविदों के सामने नई चुनौती है कि, कैस्ट्रैल को नुकसान पहुंचाये बिना ट्रैवलर्स ट्री को कैसे हटाया जाए। ट्रैवलर्स ट्री मूलतः मैडागास्कर के हैं और वर्ष 1751 में इन्हें मॉरिशस लाया गया था। यहाँ ट्रैवलर्स ट्री इतनी तेजी से फैले कि, मॉरिशस के जंगलों से मूल प्रजातियां ही नष्ट होने लगीं। परिणामस्वरुप मूल प्रजातियों पर आश्रित रहने वाले जीवों, जैसे बैट्स, फ्लाइकैचर बर्ड, बुलबुल और वाइट आइज़ के लिए भोजन की उपलब्धता कम होने लगी। फ्लोरैंस का अनुमान है कि, ट्रैवलर्स ट्री मॉरिशस की अन्य हजारों प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है पर इसे हटाना आसान नहीं है। न्यूज़ीलैंड के वैज्ञानिक, पीट मक्लैलैंड, जो शोध में शामिल नहीं है, ने कहा कि ट्रैवलर्स ट्री को हटाने से कैस्ट्रैल व गैको की आबादी घट सकती है। इसलिए ट्रैवलर्स ट्री के उन्मूलन की प्रक्रिया धीमी होनी चाहिए ताकि कैस्ट्रैल व गैको इससे तालमेल बिठा सकें।

कर्नाटक के मु.मंत्री ने पहले ही दिन से सख्ती दिखायी

पिछली भाजपा सरकार के प्रोजैक्ट्स को पैसा रिलीज़ करने पर रोक लगायी

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। कर्नाटक सरकार ने ऐसे संकेत दे दिये हैं कि वह बासवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ लगे 40 प्रतिशत सरकार आरोप की जाँच करायेगी। ज्ञातव्य है कि अभी-अभी समाप्त हुये विधानसभा चुनावों में, यह कांग्रेस के प्रचार का अहम् मुद्दा था। इस सिलसिले में, सिद्धारमैया सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिये गये किन्ही भी आदेशों के सिलसिले में फंड जारी किये जाने पर रोक लगाने के आदेश सोमवार को जारी कर दिये।

मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने आदेश जारी कर दिये कि पूर्ववर्ती सरकार तथा उसके बोर्डों और कॉर्पोरेशनों द्वारा स्वीकृत किसी भी विभाग के प्रोजैक्टों के लिये दिये जाने वाले फंड रोक दिये जायें। आदेशों में यह भी कहा गया है कि जो प्रोजैक्ट अभी तक शुरु नहीं हुये हैं, उनके सभी काम भी लम्बित रहेंगे, जिससे कि उन पर पुनर्विचार तथा उनकी समीक्षा की जा सके।

सरकार के इस निर्णय तथा एकाएक की गई इस कार्यवाही से अफसरशाही विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डर तथा निर्माण कार्य करने वाली कंपनियाँ हक्की-बक्की रह गई हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस ने इस बिन्दु को लेकर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के खिलाफ जिस तरह जोर-शोर से प्रचार किया था, उसके चलते इस प्रकार की सख्त कार्यवाही का पूर्वानुमान था। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दे दी थी कि वह इस प्रकार के सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच करेगी तथा जहाँ कहीं भी उचित एवं आवश्यक प्रतीत होगा, कार्यवाही करेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में सरकार काफी जल्दबाजी में है कि वह जनता से किये गये सभी वादों को पूरा करे, जिनमें पूर्व सरकार के प्रति सख्ती से पेश आना तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना शामिल है। प्रसंगवश बता दें कि जैसे ही नई सरकार ने शपथ ली तथा मंत्रिमण्डल की पहली बैठक हुई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जनता को पार्टी द्वारा दी गई पाँच गारन्टियों से संबंधित योजनाओं को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान कर दी थी।

कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में वादे किये थे- सभी परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति), प्रत्येक परिवार की महिला मुख्या को 2000 रू. प्रति माह की आर्थिक सहायता (गृह लक्ष्मी), बी.पी.एल. परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल (अन्न भाग्य), बेरोज़गार स्नातक युवाओं को 3000 रू. प्रति माह, बेरोज़गार डिप्लोमा धारियों (आयु वर्ग 18-25) को दो वर्ष तक 1500 रू. प्रति माह (युवा निधि) तथा सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा (शक्ति)।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस योजनाओं, जिनका अनुमानित व्यय 50,000 करोड़ रू. प्रति वर्ष होगा, के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक संसाधन जुटा लिये जायेंगे।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- सरकारी अधिकारी अंचम्भित हैं इस तत्परता से, पर, जिस जोश-खरोश से कांग्रेस ने बोम्मई सरकार पर 40 प्रतिशत सरकार होने का भरपूर आरोप लगाया, पूरे चुनाव अभियान के दौरान, ऐसे सख्त आदेश की पूरी "आशंका" थी।
- जैसा कि विदित ही है, मंत्रिमण्डल ने अपनी पहली बैठक में कांग्रेस द्वारा चुनाव अभियान के दौरान दी गयी "पांच गारंटियों" को पूरा करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
- मु.मंत्री ने इस संबंध से कहा कि, इस काम के लिये प्रति वर्ष 50 हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी, पर, कर्नाटक सरकार अपने 3.1 लाख करोड़ रू. के वार्षिक बजट में से यह राशि जरूर उपलब्ध करा सकती है।
- मु.मंत्री के अनुसार, कर्नाटक सरकार प्रति वर्ष 50 हजार करोड़ रू. का ब्याज चुकाती है, तो क्या इतनी रकम जनता के लिये उपलब्ध नहीं करा सकती।

'नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया?'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में विपक्ष के नेता

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर यह सवाल पूछा और मौजूदा सरकार पर संवैधानिक मर्यादाओं की अवमानना का आरोप लगाया।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष बायकॉट करेगा?

विपक्ष की मांग है कि, संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिये, न कि प्र.मंत्री मोदी को

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। विपक्ष ने मांग की है कि नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें तथा ऐसी संभावना है कि इस मांग को नहीं मानने की स्थिति में, विपक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नये संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर सकता है।

कांग्रेस तथा कई अन्य विपक्षी दिसम्बर 2020 में नये संसद भवन के शिलान्यास समारोह में भी शामिल नहीं हुये थे क्यों कि वे इसके समय पर सवाल खड़े कर रहे थे। दरअसल, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, करोना महामारी जोरों पर थी तथा लॉकडाउन लगाये जाने के कारण पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था।

राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिये, प्रधानमंत्री को नहीं।

- विपक्ष का तर्क है कि, संसद विधायी कार्य (कानून व नीतियां बनाने का काम) करती है। प्र.मंत्री व सरकार इन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। अतः संसद का उद्घाटन राष्ट्र की प्रथम नागरिक को करना चाहिये, न कि, कार्यकारी अधिकारी को।
- कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह कहा कि, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना भाजपा सरकार के लिये प्रतीकात्मक निर्णय है, पर, सच्चाई यह है कि, न तो वर्तमान राष्ट्रपति और न ही इनसे पूर्व राष्ट्रपति रहे व्यक्ति को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है।
- भाजपा ने पलट जवाब देते हुए कहा कि, कांग्रेस पार्टी तो केवल एक बच्चे की तरह मचल रही है। नया संसद भवन बनाना पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का स्वप्न था और अब प्र.मंत्री ने इस स्वप्न को पूरा किया, तो यह भी कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आ रहा।

इस मुद्दे पर विपक्ष के रूख पर

(शेष पृष्ठ 5 पर)

डेढ़ माह में दूसरी बार खड़गे से मिले नीतीश

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास 10, राजाजी मार्ग पर भेंट की तथा 2024 के आम चुनावों में भाजपा का सामना करने के लिये विपक्षी एकता को मजबूत करने के विषय में खड़गे तथा राहुल गांधी से बातचीत की। पिछले डेढ़ माह में यह उनकी इस प्रकार की दूसरी मीटिंग की।

- खड़गे के निवास पर हुई बैठक में राहुल भी मौजूद थे, नीतीश ने विपक्षी एकता व पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक के रोडमैप पर चर्चा की।

उन्होंने विपक्षी एकता को मजबूत करने की रूपरेखा तथा शीघ्र ही पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की संभावित मीटिंग पर चर्चा की। मीटिंग

(शेष पृष्ठ 5 पर)

मेहम चौबीसी की खाप पंचायत ने महिला कुश्ती प्रदर्शन को समर्थन दिया

राकेश टिकैत पहले ही इस प्रदर्शन व धरने की किसान आंदोलन से तुलना कर चुके हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। रैसलिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यु.एफ.आई.) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन को महिला पहलवान अगले स्तर पर ले जा रही हैं। हरियाणा की खाप पंचायत ने पदक विजेता खिलाड़ियों को अपना समर्थन दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की।

डब्ल्यु.एफ.आई. प्रमुख के खिलाफ कार्यवाही की मांग के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा दिया गया 15 दिन का अल्टीमेटम खत्म हो गया है और अब पहलवानों ने कहा है कि मेहम के चौबीसी खाप की महापंचायत में लिए गए निर्णय पर वे आगे कार्यवाही करेंगे। किसान या जंतर मंतर आने की तैयारी में हैं।

राकेश टिकैत ही पहले ही पहलवानों के आंदोलन की किसान आन्दोलन से तुलना कर चुके हैं। अब किसान भी जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं। किसान समूहों को प्रदर्शन स्थल पर आना शुरु होने के साथ ही प्रशासन से उनका टकराव होने की संभावना है।

पुलिस ने गत माह सिंह के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की थी तथा सिंह के साथ-साथ फैडरेशन के सहायक सचिव विनोद तोमर के बयान भी रिकॉर्ड किये थे। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि महिला पहलवानों द्वारा सिंह के खिलाफ की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल इन्वैस्टिगेशिव टीम (एस.आई.टी.) का गठन कर दिया गया है। पहली एफ.आई.आर. एक नाबालिग की शिकायतों पर आधारित है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की चुनौती को महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने स्वीकार किया। मैडल विजेता विनेश फोगाट ने कहा, वे ही नहीं सभी महिला खिलाड़ी नारको टैस्ट देने को तैयार हैं।
- जैसा कि विदित ही है, बृज भूषण सिंह ने शर्त रखी थी कि, वे नारको टैस्ट देंगे, अगर आंदोलनकारी विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया भी टैस्ट देने को तैयार हों।

क्या आपको कम सुनाई देता है!
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

कर्नाटक की हार से हताश भाजपा ने चुनाव तैयारी शुरू की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्य इकाइयों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें होने

- भाजपा विभिन्न राज्यों की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें कर्नाटक नतीजों की हताशा को दूर करने की कोशिश की जा रही है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कोटखावदा घटना से आक्रोशित लोगों की नारेबाजी के बीच परिजनों से मिले पायलट

घटना की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने पर किरोड़ी मीणा ने दिया डी.जी. बंगले के बाहर धरना

जयपुर, 22 मई (का.प्र.)। कोटखावदा में रविवार को सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठे परिवार के 6 लोगों को थार जीप से कुचलने के मामले में धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक वेद प्रकाश का जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की। इधर इस घटना में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने डीजीपी के बंगले पर धरना दिया। तब जाकर एफ.आई.आर. दर्ज हुई।

असल में 5 दिन पहले कोटखावदा में मदन लाल की मौत हो गई। उसके परिवार के 6 जने गंगा में अस्थि विसर्जन कर रविवार को लौटे थे और सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर परिजनों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें लेने आने वाले थे तब ही तेज गति से आ रही थार जीप ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में स्व. मदन की पत्नी सुनीता, बेटे गोलू व भाई सीताराम की मौके पर ही मौत हो गई और सीताराम की पत्नी अनिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़

- चारों मृतकों को कुल 53 लाख रूपए की सहायता राशि, दोनों घायलों को 4-4 लाख रू. देने पर परिजनों के साथ सहमति बनी है।
- इस दौरान डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने वेतन से नगद 2 लाख रू. की राशि मृतकों के परिजनों को सौंपी।
- दूसरी ओर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने चिरंजीवी योजनाओं से 10 लाख रू. की सहायता राशि का चैक सौंपकर अपना 2 महीने का वेतन पीड़ित पक्ष को देने की घोषणा की।

कोटखावदा में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के बाद परिजन एवं ग्रामीण शवों को सड़क पर रखकर रविवार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

खड़गे ने चुनाव वाले राज्यों के नेताओं को दिल्ली बुलाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावों के अगले दौर की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम के वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग 24 या 26 मई को हो सकती है। निवर्तमान तथा पूर्व

- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 24 या 26 मई को दिल्ली में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव तैयारी पर चर्चा की जाएगी।

(शेष पृष्ठ 5 पर)